न्यायमूर्ति ***अरुण कुमार त्यागी के समक्ष***

किरण वी. भास्कर - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरवादी*

2020 का CRWP नंबर 3440

31 अगस्त, 2021

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 और 227 - रिट याचिका - नाबालिग बच्चे की हिरासत ***- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका - रखरखाव - हिरासत के लिए विचार - एक माता-पिता को हिरासत देने का विदेशी अदालत का आदेश, नाबालिग का प्रत्यावर्तन तथ्यों पर का प्रभाव - तथ्यों पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में पार्टियों के बीच विवाह, और बच्चे का जन्म वहां हुआ था - नाबालिग को गुर्दे की बीमारी का निदान किया गया था - याचिकाकर्ता / पिता की सहमति के साथ सर्जरी के लिए मां / प्रतिवादी के साथ भारत लाया गया था - संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर रहने के लिए सहमति थी 26.09.2019 तक - सर्जरी के बाद प्रतिवादी यात्रा सहमति का उल्लंघन करते हुए नाबालिग बच्चे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने में विफल रहा - इस बीच, अर्कांसस, अमेरिका के सर्किट कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को नाबालिग की प्राथमिक हिरासत और नियंत्रण प्रदान किया - माना जाता है कि नाबालिग की हिरासत को बहाल करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट जारी की जा सकती है। लेकिन नाबालिग के हित और कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या होगा - बाल कल्याण को पैसे या केवल भौतिक आराम से नहीं मापा जाना चाहिए - बच्चे के नैतिक और धार्मिक कल्याण को शारीरिक भलाई के साथ माना जाना चाहिए - इसके अलावा, विदेशी अदालत का आदेश एक कारक है, जिसे माना जाना चाहिए, लेकिन यह नाबालिग बच्चे के प्रत्यावर्तन के प्रश्न से अलग नहीं है - इस प्रश्न को भी बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण की कसौटी पर तय किया जाना है - याचिका में यह कहते हुए अनुमति दी गई है कि नाबालिग के कल्याण और सर्वोत्तम हित के लिए उसे संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस कर दिया जाए - अभिभावक नियुक्त करने/ माता-पिता में से किसी एक को संरक्षण सौंपने का सवाल संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिया जाना है।***

यह निर्धारित किया गया *कि* जब भी किसी नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित कोई सवाल उठता है, चाहे वह अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 आदि के तहत या उससे पहले नाबालिग बच्चे की हिरासत के लिए याचिका पर फैमिली कोर्ट / अभिभावक न्यायाधीश के समक्ष हो

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, मामले को पार्टियों के कानूनी अधिकारों के विचार पर नहीं बल्कि नाबालिग के हित और कल्याण के एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर तय किया जाना है।

(पैरा 17)

आगे कहा गया कि बच्चे के कल्याण को केवल पैसे से नहीं मापा जाना चाहिए और न ही केवल भौतिक आराम से। 'कल्याण' शब्द को इसके व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसकी शारीरिक भलाई पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह के बंधन की अवहेलना की जा सकती है। (पर लिंडले, मैकग्राथ में एलजे, (1893) 1 सीएच 143)। कल्याण एक सर्वव्यापी शब्द है। इसमें भौतिक कल्याण शामिल है, दोनों एक सुखद घर और आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए संसाधनों की पर्याप्तता के अर्थ में और यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की पर्याप्तता के अर्थ में कि अच्छा स्वास्थ्य और उचित व्यक्तिगत गौरव बनाए रखा जाता है। हालांकि, जबकि भौतिक विचारों का अपना स्थान है, वे द्वितीयक मामले हैं। अधिक महत्वपूर्ण स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और मार्गदर्शन, गर्म और दयालु रिश्ते हैं, जो बच्चे के अपने चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं।

(पैरा 18)

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भारत ने अंतर-राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 या माता-पिता की जिम्मेदारी और बच्चों के संरक्षण पर हेग कन्वेंशन, 1996 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर मामलों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता को चुनौती देने वाली अपीलों की संख्या में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चों के प्रत्यावर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के प्रश्न पर विचार किया है। जिन्हें विदेशों से निकालकर भारत लाया गया था, जिस देश से उन्हें हटाया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया है कि उच्च न्यायालय बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार को ध्यान में रखते हुए हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है और यहां तक कि विदेशी न्यायालय के आदेश को भी बच्चे के कल्याण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

(पैरा 23)

आगे कहा गया कि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में विदेशी न्यायालय का पहले से मौजूद आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में माना जाने वाला एक कारक है, लेकिन यह नाबालिग बच्चे के प्रत्यावर्तन के सवाल को बाधित नहीं करता है ताकि इसे अनुमति दी जा

सके, जिस प्रश्न को नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के परीक्षण पर तय किया जाना है।
(पैरा 26)

आगे कहा गया कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए और सारांश जांच के आधार पर, मेरा विचार है कि यह नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित में होगा कि नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस लाने के लिए आदेश पारित किया जाए। जहां से उसे हटाया गया था और यह उचित होगा कि अभिभावक की नियुक्ति/नाबालिग बच्चे को माता-पिता में से किसी एक को सौंपने के प्रश्न को संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा कल्याण और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सर्वोच्च विचार के आधार पर निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए।
(पैरा 53)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शादान फरासत, अधिवक्ता अर्जुन श्योराण और अधिवक्ता नेहा सोनवणे।

मुनीश डडवाल, सहायक एजी, हरियाणा राज्य उत्तरदाता संख्या 1 के लिए

प्रतिवादी नंबर 2 से 4 की ओर से सतीश टम्टा, सीनियर अधिवक्ता अनिमेष शर्मा और अधिवक्ता विक्रमादित्य भास्कर

अनिल मल्होत्रा, अधिवक्ता न्यायालय मित्र के रूप में।

अरुण कुमार त्यागी, जे।

(मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाने के लिए लिया गया है।)

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिवादियों को नाबालिग बच्चे-आदित्य किरण (इसके बाद 'नाबालिग बच्चे' के रूप में संदर्भित) की रिहाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे (वर्तमान याचिका दायर करने के समय लगभग चार वर्ष की आयु) को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की अवैध हिरासत से रिहा करें और उसकी हिरासत याचिकाकर्ता को सौंप दें। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की भी मांग की कि प्रतिवादी नंबर 1 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 2 और 4 याचिकाकर्ता को अपने बेटे के साथ दैनिक आधार पर फोन और चलचित्र सम्प्रेषण पर संवाद करने की अनुमति दें और सुविधा प्रदान करें, जो याचिकाकर्ता और उसके बेटे दोनों के लिए सुविधाजनक हो।

नाबालिग बच्चे के याचिकाकर्ता-पिता का प्रत्यावर्तन दावा।

(2) संक्षेप में कहा गया है, याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि याचिकाकर्ता, जो कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर है, वर्तमान में वॉलमार्ट लैब्स, बेंटनविले, संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद 'यूएसए' के रूप में संदर्भित) में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। याचिकाकर्ता अमेरिका के अरकंसास स्थित बेंटन कंट्री का स्थायी निवासी है।

(2.1) याचिकाकर्ता ने 13.01.2011 को न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवादी नंबर 2 के साथ शादी की। आदित्य किरण का जन्म 21.01.2016 को बेंटनविले, अरकंसा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने परिवार को बसाने के लिए अमेरिका के अर्कांसस के सेंटरटन में घर खरीदा। अमेरिका के अरकंसास के बेंटनविले में 'ब्राइट बिगिनिंग्स' में नाबालिग बच्चे को प्री-स्कूलिंग के लिए भर्ती कराया गया था।

(2.2) माना मेडिकल एसोसिएट्स की दिनांक 31.01.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग बच्चे को हाइड्रोनफ्रोसिस नामक जन्मजात स्थिति का निदान किया गया था जो गुर्दे को प्रभावित करता है जिसे सर्जरी द्वारा सुधार की आवश्यकता होती है। अरकंसास में सर्जरी के लिए तारीखों की अनुपलब्धता के कारण, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 ने मैक्स अस्पताल, साकेत, नई दिल्ली में डॉ अनुराग कृष्णा द्वारा भारत में सर्जरी करने का फैसला किया।

(2.3) अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक बच्चे के अपहरण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, याचिकाकर्ता की सहमति उसके बेटे को अकेले प्रतिवादी नंबर 2 के साथ यात्रा करने के लिए आवश्यक थी। याचिकाकर्ता ने इसके लिए सहमति दी और केवल 26.09.2019 तक यूएसए के बाहर रहने के लिए दिनांक 04.02.2019 को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। प्रतिवादी नंबर 2 नाबालिग बच्चे के साथ 05.02.2019 को भारत आया था और उसे 26.09.2019 को अमेरिका लौटना था, जिस तारीख के लिए वापसी टिकट बुक किए गए थे। याचिकाकर्ता ने सर्जरी और भारत में रहने के खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक खर्चों का भी भुगतान किया था।

(2.4) सर्जरी 14.03.2019 को हुई थी। याचिकाकर्ता मार्च, 2019 में प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे के साथ शामिल हुआ था, लेकिन अपनी नौकरी में भाग लेने के लिए अमेरिका वापस चला गया। याचिकाकर्ता जुलाई, 2019 तक प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे के साथ नियमित संचार में रहा, जब प्रतिवादी नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ नियमित संचार बंद कर दिया और नाबालिग बच्चे के स्वास्थ्य और प्रगति के बारे में अपडेट प्रदान करना बंद कर दिया और याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं दी।

(2.5) प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता द्वारा दी गई यात्रा सहमति का उल्लंघन करते हुए 26.09.2019 को नाबालिग बच्चे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने में विफल रहा।

प्रतिवादी नंबर 2 ने दावा किया कि वह आगे की चिकित्सा जांच के लिए नाबालिग बच्चे के साथ वापस रह रही थी, लेकिन नाबालिग बच्चे की चिकित्सा स्थिति के बारे में विवरण प्रदान करने के उसके अनुरोध का जवाब नहीं दिया। प्रतिवादी नंबर 2 के साथ संवाद करने में असमर्थता से उत्पन्न चिंताओं के कारण, याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र पूछताछ की और पता चला कि प्रतिवादी नंबर 2 अत्यधिक शराब के उपयोग में संलग्न है और विवाहेतर संबंध बना रहा है और प्रतिवादी नंबर 2 आइवरी टावर्स, गुरुग्राम में अलग अपार्टमेंट में रह रहा था, जहां उसने नाबालिग बच्चे को पूरे दिन एक नौकरानी की देखभाल में छोड़ दिया। प्रतिवादी नंबर 2 को वेंकटेश्वर अस्पताल, द्वारका, दिल्ली में रोजगार मिला था।

(2.6) याचिकाकर्ता ने अमेरिकी दूतावास से सहायता मांगी, जिसने 17.12.2019 को प्रतिवादी नंबर 2 के माता-पिता के निवास पर कल्याणकारी यात्रा की और यात्रा की रिपोर्ट से पता चला कि प्रतिवादी नंबर 2 ने कई भ्रामक बयान दिए थे। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने 17.09.2019 के एक प्रमाण पत्र की तस्वीर भी भेजी, जिस पर कथित तौर पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर हैं। याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.01.2020 के ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट पर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 25.12.2019 के ई-मेल के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 ने उसके पिता द्वारा पहले से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में 10,00,000 रुपये की राशि की मांग की, लेकिन नाबालिग बच्चे के साथ यूएसए लौटने के बारे में उल्लेख नहीं किया।

(2.7) याचिकाकर्ता ने यूएसए के बाहर नाबालिग बच्चे की गलत हिरासत के कारण बच्चे की प्राथमिक देखभाल, संरक्षण और नियंत्रण की मांग करते हुए 30.01.2020 को बेंटन काउंटी, अर्कांसस के सर्किट कोर्ट के समक्ष अलग रखरखाव के लिए याचिका दायर की, उपरोक्तन्यायालय ने दिनांक 03.02.2020 को एकपक्षीय आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि उपरोक्तन्यायालय के पास पार्टियों और विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र था और हिरासत के दावे के निर्णय के लिए उचित स्थान था और याचिकाकर्ता को बच्चे की प्राथमिक देखभाल, संरक्षण और नियंत्रण प्रदान किया और प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चे को तुरंत याचिकाकर्ता को सौंप दिया जाए, यह देखते हुए कि बेटे से पिता का अलगाव बेटे की भलाई के लिए हानिकारक होगा। बेटे का। आदेश 24.02.2020 को वितरित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ता से दूर रखा जा रहा है, जो कानूनी अभिभावक है, जो जानबूझकर अमेरिकी अदालत के आदेश की अवज्ञा कर रहा है।

प्रतिवादी नंबर 1-हरियाणा राज्य द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया

(3) प्रतिवादी संख्या 1- हरियाणा राज्य द्वारा याचिका का कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

<u>प्रतिवादी नंबर 2-मां और प्रतिवादी नंबर 3 और 4-नाबालिग बच्चे के नाना-नानी का प्रतिद्वंद्वी दावा</u>।

(4) दिनांक 12.07.2020 के उत्तर के तहत याचिका को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा चुनौती दी गई है। जवाब में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने यह खुलासा नहीं किया है कि नाबालिग बच्चे की गंभीर चिकित्सा सर्जरी हुई है और वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सर्जरी केवल दाईं किडनी की की गई है, जबकि बाएं गुर्दे की सर्जरी की भी आवश्यकता थी, लेकिन नाबालिग बच्चे की उम्र कम होने के कारण उसकी बाईं किडनी का ऑपरेशन नहीं किया गया है। भारत में डॉक्टरों की पूरी टीम इस पर कड़ी नजर रख रही है। नाबालिग बच्चे को नियमित फॉलोअप और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है जो केवल प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किया जा सकता है क्योंकि वह समस्या के बारे में पूरी तरह से अपडेट है और लगातार नाबालिग बच्चे के डॉक्टरों के संपर्क में है। मानक चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा सलाह की उपलब्धता में आसानी भारत में बेहतर है। अमेरिका में नाबालिग बच्चे की तत्काल सर्जरी के लिए कोई शुरुआती तारीख नहीं दी जा रही थी और उसे भारत ले जाना पड़ा। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अच्छी चिकित्सा देखभाल सुविधा प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। यह तथ्य कि प्रतिवादी नंबर 2 के परिवार में डॉक्टर हैं, बेहद फायदेमंद है। प्रतिवादी नंबर 4, प्रतिवादी नंबर 2 की मां, जिसके साथ नाबालिग बच्चा रहता है, एक डॉक्टर है। उसका भाई भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और उत्तरदाताओं नंबर 2 से 4 के करीब रहता है। प्रतिवादी नंबर 2 का भाई भी एक डॉक्टर है। नाबालिग बच्चे का भारत के गुरुग्राम में रहना हित में है।

(4.1) नाबालिग बच्चा खुशहाल घर में रह रहा है, प्यार करने वाले परिवार और दोस्तों से घिरा हुआ है, जैसा कि अमेरिकी दूतावास की रिपोर्ट से पता चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, याचिकाकर्ता के पास शायद ही कोई परिवार और दोस्त थे और नाबालिग बच्चा उस कंपनी से रहित था जिसकी उसे उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता थी। नाबालिग बच्चे के दिल्ली और गुड़गांव में दोस्त हैं। उनके पास भारत में विभिन्न प्रकार की पूजा और त्योहारों का जश्न मनाने का एक अद्भुत अवसर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी नहीं किया जा सकता था। वह हर दिन अपने नाना-नानी के घर मंदिर जाता है, जहां वह रहता है। भारत में उनकी मजबूत जड़ें हैं। उन्होंने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ भारत की यात्रा की है और भारत में लंबे समय तक रहे हैं। नाबालिग बच्चे को पहले 2018 में प्री-स्कूल में और फिर 2019 में और अब 2020 में याचिकाकर्ता की पूर्व सहमति से नर्सरी स्कूल में नामांकित किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 हमेशा से योजना बना रहे थे कि प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे भारत में स्थानांतरित हो जाएंगे। नाबालिग बच्चे ने 2018 में भारत में प्री-स्कूलों में भाग लिया था

और अब वह श्री राम स्कूल, गुरुग्राम, भारत में नर्सरी में जा रहा है, जैसा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच बहुत पहले तय किया गया था।

(4.2) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 को मानसिक यातना, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के अधीन किया है और भूमि में निवेश किए जाने वाले धन के लिए उसे लगातार परेशान किया है। याचिकाकर्ता एक बार इतना हिंसक हो गया कि प्रतिवादी नंबर 2 को 02.11.2018 को अर्कांसस, यूएसए में महिला आश्रय को फोन करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को गलत तरीके से याचिका में पक्षकार के रूप में सूचीबद्ध किया ताकि प्रतिवादी नंबर 2 पर दबाव डाला जा सके कि वह उसे दिए गए धन को वापस न मांगे। यात्रा सहमति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यात्रा योजना में किसी भी बदलाव पर माता-पिता दोनों द्वारा चर्चा और सहमति दी जाएगी और यह याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे पर पूर्ण अधिकार नहीं देता है। याचिकाकर्ता ने लिखित और मौखिक रूप से स्वीकार किया है कि उसेके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति का पता चला था, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे नाबालिग बच्चे पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(4.3) उसकी शादी से लेकर अब तक के सभी खर्च और नाबालिग बच्चे की सर्जरी का खर्च प्रतिवादी नंबर 3 और 4 द्वारा वहन किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने खर्चों का ख्याल रखने की शालीनता भी नहीं जताई है और अपने स्वयं के हवाई टिकटों का भी प्रतिवादी नंबर 3 और 4 द्वारा ख्याल रखा गया था। याचिकाकर्ता ने लगातार मांग की है और भारत में बसने के लिए भारत में संपत्ति खरीदने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा धन का भुगतान किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दिए गए धन और व्यय को याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें वापस नहीं किया गया है।

(4.4) याचिकाकर्ता हमेशा नाबालिग बच्चे को उसके दादा-दादी से दूर रखने की कोशिश करता था। 14.03.2019 को नाबालिग बच्चे की सर्जरी के बाद भी, याचिकाकर्ता या उसकी मां उससे मिलने नहीं गई और उसकी भलाई के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई गई। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के चरित्र पर आक्षेप लगाया है जो एक पवित्र रिश्ते के अपरिवर्तनीय टूटने का कारण बनता है।

(4.5) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने भी प्रारंभिक आपत्तियां ली हैं कि रिट याचिका न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और रिट याचिका नाबालिग बच्चे की हिरासत के लिए नहीं है क्योंकि किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। भारतीय अदालतों के पास नाबालिग बच्चे के हिरासत में विवादों से निपटने का अधिकार है, भले ही एक विदेशी अदालत ने माता-पिता में से किसी एक के पक्ष में आदेश पारित किया हो। नाबालिग बच्चा याचिकाकर्ता की सहमति से प्रतिवादी नंबर 2 की कानूनी हिरासत में है। रिट याचिका काफी देरी से दायर की गई है।

(4.6) प्रतिवादी संख्या 2 को सुने बिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए एकतरफा अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी नंबर 2 को अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत से आधिकारिक समन प्राप्त नहीं हुआ है और वह वहां मामले को चुनौती देगा। किसी भी मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए हिरासत का एकपक्षीय अंतरिम आदेश न्यायालय के सिद्धांत के समूह द्वारा परिकल्पित आदेश नहीं है। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (ए) के तहत, प्रतिवादी नंबर 2 नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है, जो साढ़े चार साल का है।

(4.7) अपने लिखित बयान में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने गुरुग्राम में 08.08.2011 को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 की भारतीय शादी और याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 और 4 से भूमि आदि की खरीद के लिए ऋण लेने और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच तनावपूर्ण संबंधों सहित घटनाओं का संक्षिप्त इतिहास भी दिया है।

(4.8) गुण-दोष के आधार पर अपने लिखित बयान/उत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता एच-1बी वीजा धारक है और उसके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि याचिकाकर्ता को स्थायी नागरिकता मिलेगी। प्रतिवादी नंबर 2 पांच साल की उम्र तक नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है। नाबालिग बच्चा याचिकाकर्ता की सहमति से भारत में रह रहा है, जो खुद चाहता था कि नाबालिग बच्चा और प्रतिवादी नंबर 2 भारत वापस चले जाएं और वहां बस जाएं ताकि वह अधिक पैसा बचा सके और जमीन खरीद सके। 04.09.2019 के अपने ई-मेल में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि "हमने फैसला किया कि दूर रहने का यह बलिदान आपके लिए अपना शारीरिक चिकित्सा कैरियर शुरू करने के लिए जरूरी है"। 11.01.2019 के व्हाट्सएप संदेश में याचिकाकर्ता ने लिखा "भारत जाओ, महनत करो, पैसा कमाओ, और हम एक अद्भुत घर बनाएंगे"। 26.10.2019 के अपने ईमेल में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि "आपने सिफारिश की थी कि अपने माता-पिता के साथ रहने के कुछ महीनों के बाद, आप एक अपार्टमेंट में चले जाएंगे, इसलिए मैं जब भी आप लोगों से मिलने आ सकता हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ। 11.07.2019 के अपने व्हाट्सएप संदेश में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह चाहता था कि प्रतिवादी नंबर 2 भारत जाए और काम करे। शराब के अत्यधिक उपयोग और विवाहेतर संबंध के आरोप निराधार और बिना किसी सबूत के हैं।

(4.9) जनवरी, 2019 में नाबालिग बच्चे को हाइड्रोनफ्रोसिस का निदान किया गया था। दिल्ली आने के बाद ही कई नैदानिक परीक्षण किए गए (जैसे डीटीपीए, एमसीयू और अल्ट्रासाउंड) और यह पाया गया कि नाबालिग बेटा यूरेटेरो-पेल्विक जंक्शन रुकावट (यूपीजे)

से पीड़ित था, जो उनके मामले में एक जन्मजात समस्या थी क्योंकि उनके पास 'घोड़े की नाल किडनी' है जो हाइड्रोनफ्रोसिस का कारण बनती है। याचिकाकर्ता ने एक भूमि सौदा पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से बैंगलोर, भारत की यात्रा की और फिर नाबालिग बच्चे की सर्जरी के लिए दिल्ली का दौरा करने आया। वह नाबालिग बेटे को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराने से एक दिन पहले ही पहुंच गया था। सर्जरी के बाद वह कुछ दिनों के लिए रहे और फिर से बैंगलोर के लिए रवाना हो गए और बाद में फिर से दिल्ली गए और अंत में बैंगलोर के माध्यम से यूएसए के लिए रवाना हो गए। याचिकाकर्ता ने अमेरिका जाने से पहले प्रतिवादी नंबर 2 के पास कोई पैसा नहीं छोड़ा। आज तक, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे की कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं ली है क्योंकि उनके सभी खर्च प्रतिवादी नंबर 3 और 4 द्वारा वहन किए गए हैं। प्रतिवादी नंबर 3 और उसके नाबालिग बच्चे की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा के सभी खर्च प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा वहन किए गए थे। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने तदनुसार याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

(5) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दायर किया है, जिसमें उनके दावे को दोहराया गया है।

(6) मैंने श्री शादान फरासत अधिवक्ता द्वारा संबोधित तर्कों को सुना है, जिसमें श्री अर्जुन श्योराण, अधिवक्ता और सुश्री नेहा सोनवणे, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, श्री मुनीश डडवाल, सहायक ए जी हरियाणा राज्य शामिल हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए और श्री सतीश टम्टा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिमेष शर्मा, अधिवक्ता और श्री विक्रमादित्य भास्कर, प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के विद्वान वकील और श्री अनिल मल्होत्रा, न्यायमित्र ने जानकारी प्राप्त की और संबंधित रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ।

(7) याचिकाकर्ता के वकील श्री शादान फरासत ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं: -

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

(7.1) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 की शादी 13.01.2011 को न्यूयॉर्क, यूएसए में हुई थी।

(7.2) नाबालिग बच्चे का जन्म 21.01.2016 को बेंटन काउंटी, अर्कांसस में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, याचिकाकर्ता का बेटा जन्म से अमेरिका का नागरिक है, और उसके पास यू.एस.ए. पासपोर्ट है जो 13.10.2021 तक वैध है।

(7.3) याचिकाकर्ता के बेटे को जनवरी, 2019 में हाइड्रोनफ्रोसिस का पता चला था, जो एक गुर्दे की स्थिति है जिसे सर्जरी द्वारा सुधार की आवश्यकता थी।

(7.4) अमेरिका में सर्जरी स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 ने मैक्स अस्पताल साकेत में डॉ अनुराग कृष्णा द्वारा भारत में सर्जरी करने का फैसला किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा सहमति फॉर्म निष्पादित किया गया था, जिसमें बच्चे को 05.02.2019 और 26.09.2019 की तारीखों के बीच प्रतिवादी नंबर 2 के साथ भारत की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। यात्रा सहमति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "इस योजना में किसी भी बदलाव पर चर्चा की जाएगी और दोनों माता-पिता द्वारा सहमति दी जाएगी"।

(7.5) नाबालिग बच्चे ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ 05.02.2019 को यात्रा सहमति के संदर्भ में भारत की यात्रा की। 14.03.2019 को मैक्स अस्पताल, साकेत में उनकी सुधारात्मक सर्जरी हुई, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने भारत के लिए उड़ान भरी। इसके बाद, सर्जरी के बाद, याचिकाकर्ता काम पर फिर से शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया।

(7.6) बच्चा सर्जरी से ठीक हो गया, और अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह सर्जन डॉ. अनुराग कृष्ण के दिनांक 17.09.2019 के प्रमाण पत्र में दर्ज है। नतीजतन, कोई चिकित्सा आवश्यकता नहीं है जिसके लिए बच्चे को भारत में निरंतर रहने की आवश्यकता हो।

(7.7) प्रतिवादी संख्या 2 ने 26.09.2019 तक नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस नहीं करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहमति का उल्लंघन किया (पारस्परिक रूप से सहमत तिथि)। तब से, उसने याचिकाकर्ता द्वारा अमेरिका लौटने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे भारत में अपनी अवैध हिरासत में रखा है।

(7.8) याचिकाकर्ता ने बेंटन काउंटी, अर्कांसस (उपयुक्त न्यायिक न्यायालय) के सर्किट कोर्ट के समक्ष दिनांक 30.01.2020 को अलग से रखरखाव के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें अमेरिका के बाहर गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के कारण अपने नाबालिग बच्चे की प्राथमिक देखभाल, नियंत्रण और संरक्षण की मांग की गई।

(7.9) क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत यानी बेंटन काउंटी, अर्कांसस के सर्किट कोर्ट ने 03.02.2020 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे की प्राथमिक देखभाल, संरक्षण और नियंत्रण प्रदान किया गया, और प्रतिवादी नंबर 2 को अगले आदेश तक बच्चे को तुरंत याचिकाकर्ता को वापस करने का निर्देश दिया गया। यह एक अंतरिम आदेश है और बच्चे की हिरासत का अंतिम निर्धारण नहीं है। आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि मामले को किसी भी पक्ष के अनुरोध पर लिया जाएगा।

(7.10) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 को ईमेल के माध्यम से क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत द्वारा पारित 03.02.2020 के आदेश की एक प्रति दि जो की न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर हेग कन्वेंशन, 1965 के अनुसार थी।

(7.11) इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भारत में नाबालिग बच्चे को उसकी अवैध हिरासत में रखना जारी रखने के कारण, क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत यानी बेंटन काउंटी, अर्कांसस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

जांच का दायरा

(7.12) अंतर्राष्ट्रीय माता-पिता के बाल संरक्षण मामलों में यह स्थापित कानून है कि जहां एक विदेशी अदालत हिरासत के मुद्दे पर जब्त है और बच्चे ने भारत में बहुत लंबा समय नहीं बिताया है, भारतीय अदालत की भूमिका यह जांचने के लिए एक सारांश जांच करने तक सीमित है कि क्या क्षेत्राधिकार विदेशी न्यायालय के आदेशों के अनुसार बच्चे के मूल देश लौटने पर कोई नुकसान होगा। किसे हिरासत में लिया जाना चाहिए, इसका कोई विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत का कार्य है।

(7.13) वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2-4 द्वारा कोई विशिष्ट दलील नहीं है कि याचिकाकर्ता एक बुरा पिता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है कि नाबालिग बच्चे को सीमित अवधि (05.02.2019- 26.09.2019) के लिए सर्जरी और बाद में स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत लाया गया था। इसके बावजूद, बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस नहीं किया गया है, भले ही वह ठीक हो गया है और भारत में उसके निरंतर रहने की आवश्यकता नहीं है।

(7.14) क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत यानी बेंटन काउंटी, अर्कांसस की सर्किट कोर्ट याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच हिरासत विवाद को जब्त कर चुकी है, और 03.02.2020 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि बच्चे को भारत वापस कर दिया जाए। यह आदेश एक अंतरिम आदेश की प्रकृति में है और प्रतिवादी नंबर 2 के लिए क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत के समक्ष नाबालिग बच्चे की हिरासत के सवाल सहित अपने मुद्दे को उठाने के लिए खुला छोड़ देता है।

(7.15) नतीजतन, यह न्यायालय ***नीलांजन भट्टाचार्य बनाम स्टेशन हाउस अधिकारी कोरमगला ओर अन्य***[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित शर्तों साथ ही साथ इस माननीय न्यायालय द्वारा ***सी.आर.डब्ल्यू.पी. - 7400-2020 में परमिंदर कौर बरार***

[1] 2020 (2) DMC 220

बनाम पंजाब राज्य और अन्य, दिनांक 17.12.2020, द्वारा उल्लिखित शर्तों पर बच्चे को उसके मूल देश संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटने का निर्देश है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा आधारहीन दावे

(7.16) यह दावा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उसे दूसरी सर्जरी की आवश्यकता है, स्पष्ट रूप से गलत है, जैसा कि बच्चे के सर्जन डॉ. अनुराग कृष्ण के दिनांक 17.09.2019 के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने डॉ. अनुराग कृष्णा से भी बात की है, जिन्होंने कहा है कि बच्चे को अमेरिका लौटने से कोई नहीं रोक रहा है। याचिकाकर्ता ने हलफनामे में इसकी पुष्टि की है।

(7.17) प्रतिवादी संख्या 2 ने संदर्भ से बाहर कुछ व्हाट्सएप संदेशों पर भरोसा किया है जो झूठा आरोप लगते है कि याचिकाकर्ता आतमहत्यावृति का है। यह आरोप याचिकाकर्ता की 21.10.2020 की विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से गलत साबित होता है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि "[याचिकाकर्ता] किसी भी न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल समस्याओं से मुक्त है और उसे इस समय कोई निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। वह अवसाद, चिंता से मुक्त है और कोई आत्मघाती विचारधारा की रिपोर्ट नहीं करता है"।

(7.18) अमेरिकी दूतावास कल्याण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कल्याण रिपोर्ट बाल संरक्षण मूल्यांकन नहीं है और आगे यह कहते हुए इसे योग्य बनाती है कि विजिटिंग परामर्श दाता अधिकारी बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य में प्रशिक्षित नहीं है जैसा कि अस्वीकरण में उल्लिखित है।

(7.19) याचिकाकर्ता के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए आवश्यक कौशल भी है, और इसे हलफनामे पर रखा है। उसके पास स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प भी है, जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर पूरे समय बच्चे की देखभाल कर सके। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की मां श्रीमती उषा हनुमंथराया के पास 23.02.2024 तक वैध अमेरिकी वीजा है और उन्होंने इस माननीय न्यायालय में नाबालिग बच्चे की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की है, जो ***नीलांजन भट्टाचार्य*** *(उपरोक्त)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में भी एक प्रासंगिक कारक था।

(7.20) बच्चा एक अमेरिकी नागरिक है; अरकंसास के बेंटन काउंटी में क्षेत्राधिकार विदेशी अदालत पहले से ही हिरासत की कार्यवाही से ग्रस्त है। बच्चे की हिरासत के संबंध में भारत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। यह परीक्षण कि बच्चे को अपने मूल अधिकार क्षेत्र में लौटने पर नुकसान होगा, संतुष्ट नहीं है। नतीजतन, यह माननीय न्यायालय ***संक्षिप्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग*** *करते हुए नीलांजन भट्टाचार्य* (उपरोक्त) और ***परमिंदर कौर बरार*** *(उपरोक्त)* के मामले में समान शर्तों पर नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यावर्तित करने का निर्देश दे सकता है।

(7.21) अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने इन मुकदमों की दलीलों पर भरोसा किया है, **नीलांजन भट्टाचार्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**[2], ***नीलांजन भट्टाचार्य बनाम स्टेशन हाउस ऑफिसर कोरामगला और अन्य*** [3], ***17.12.2020 को*** **निश्चित** ***सीआरडब्ल्यूपी-7400-2020 'परमिंदर कौर बरार बनाम पंजाब राज्य और अन्य'; यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य***[4], ***सूर्य वदनन बनाम तमिलनाडु राज्य***[5], ***डॉ. वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ***[6], ***लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली***[7], ***संदीप कौर ढिल्लों बनाम पंजाब राज्य***[8] ***और श्रीमती एलिजाबेथ दिनशॉ*** **बनाम** ***अरवंद एम. दिनशॉ और अन्य***[9]

(8) श्री मुनीश डडवाल, सहायक। एजी, हरियाणा विद्वान राज्य वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी नंबर 1-हरियाणा राज्य इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करेगा।

(9) प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के वरिष्ठ वकील श्री सतीश टम्टा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं: -

(9.1) याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है और साफ हाथों से संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत से भी संपर्क नहीं किया है। याचिकाकर्ता के आचरण को उजागर करने वाले कुछ तथ्यों को उनके द्वारा छिपाया गया है। याचिकाकर्ता की जोड़-तोड़ की प्रकृति स्पष्ट है, एक छोर पर उसने वर्तमान मामला यह कहते हुए दायर किया है कि नाबालिग बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, जबकि उसके बयानों से यह स्पष्ट है कि वह जानता था और वास्तव में चाहता था कि प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे अपने घर पर प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के साथ रहें। जो प्रतिवादी नंबर 2 को काम शुरू करने में मदद करेगा ताकि उनके खातों में अधिक पैसा आ सके।

(9.2) संयुक्त राज्य अमेरिका में हिरासत का मामला प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा याचिकाकर्ता को ई-मेल करने के तुरंत बाद दायर किया गया था, जिसमें उनसे प्रतिवादी नंबर 3 को पैसा वापस करने का अनुरोध किया गया था, जो जमीन खरीद के लिए लिया गया था, ईमेल 14.01.2020 को भेजा गया था और मामला 30.01.2020 को दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 दोनों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर याचिकाकर्ता ने माना है कि वह नाबालिग बच्चे का सबसे अच्छा / बेहतर अभिभावक है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है

---

[2] 2020 (4) RCR (Civil) 660
[3] 2020 (2) DMC 220
[4] 2020 (3) SCC 67
[5] 2015 (5) SCC 450
[6] 2020 (1) SCC 147
[7] 2019 (7) SCC 311
[8] AIR 2016 (NOC 707) 328
[9] 1987 (1) SCC 42

कि प्रतिवादी नंबर 2 को किस उद्देश्य से भारत और नाबालिग बच्चे के साथ भेजा गया था।

नाबालिग बच्चे की चिकित्सा स्थिति।

(9.3) अमेरिका में 31.01.2019 को हाइड्रोनफ्रोसिस नामक नाबालिग बच्चे की चिकित्सा स्थिति के निदान के बाद प्रतिवादी नंबर 2 की अपने नाबालिग बच्चे के साथ भारत की यात्रा पूर्व नियोजित थी।

(9.4) नाबालिग बच्चे की एक किडनी का ऑपरेशन 14.03.2019 को मैक्स अस्पताल साकेत, दिल्ली में किया गया था।

(9.5) हालांकि 31.01.2020 को अंतिम रिपोर्ट में मामूली सुधार देखा गया है, लेकिन कोई चूक नहीं हो सकती है क्योंकि यह नाबालिग बच्चे के जीवन के लिए बेहद घातक हो सकता है क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि वह अत्यधिक पानी का सेवन कर सकता है जिससे उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इस तरह की चरम चिकित्सा देखभाल और पर्यवेक्षण प्रदान करना संयुक्त राज्य अमेरिका में संभव नहीं होगा।

याचिकाकर्ता का भारत में बसने का दृष्टिकोण।

(9.6) नाबालिग बच्चे को पूरी तरह से उसकी भारतीय जड़ों से जोड़े जाने की संभावना एक कारण था कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 और उनके नाबालिग बच्चे को स्थायी रूप से बचने के लिए भारत भेजने का निर्णय लिया। सगाई और शादी सभी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई। यहां तक कि नाबालिग बच्चे का पहला जन्मदिन भी भारत में मनाया गया।

(9.7) नाबालिग बच्चे को उसकी जड़ों से अलग करना याचिकाकर्ता के लिए अत्यधिक चिंता का कारण था। वह अमेरिकी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर से संतुष्ट नहीं थे। दिनांक 24.01.2019 के रिकॉर्डेड काउंसलिंग सत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता चाहता है कि उसका बच्चा भारत में पढ़ाई करे।

(9.8) याचिकाकर्ता के निर्देश पर प्रतिवादी नंबर 2 ने पहले भी 2017 और 2018 में नाबालिग बच्चे के साथ भारत की यात्रा की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में स्थायी रूप से बसना था। 2018 में नाबालिग बच्चे को भी भारत में प्रीस्कूल में नामांकित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2019 में भारत में रहते हुए खुद प्रीस्कूल "पल्लवन" का चयन किया था और तदनुसार प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रवेश के लिए भुगतान किया था।

(9.9) याचिकाकर्ता ने लगातार भारत में अधिक से अधिक जमीन खरीदी, विशेष रूप से बैंगलोर में, जो उसका गृह शहर है क्योंकि वह लगातार भारत में बसना चाहता था।

प्रतिवादी नंबर 2 के साथ अपनी हर संभव बातचीत में उन्होंने उसे प्रतिवादी नंबर 3 से जमीन खरीदने के लिए धन मांगने के लिए प्रेरित करना सुनिश्चित किया।

(9.10) भारतीय जीवन शैली पर जोर याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने 15.06.2020 के अतिरिक्त हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

(9.11) यात्रा की योजना बनाना और भारत में बसना दोनों पक्षों द्वारा लिया गया एक संयुक्त निर्णय था, वास्तव में याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 को भारत में काम शुरू करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति था, जिसे पार्टियों के बीच 11.01.2019 को व्हाट्सएप बातचीत में कैद किया गया है।

(9.12) याचिकाकर्ता द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाई के कारण उन्होंने समय-समय पर प्रतिवादी नंबर 2 को भारत जाने और वहां बसने और काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया था।

याचिकाकर्ता की तेजमिजाज/आत्मघाती प्रकृति।

(9.13) याचिकाकर्ता को मनमौजी समस्याएं हैं और वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, उसका गुस्सा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी और अपने नाबालिग बच्चे की जान का डर हो सकता है, एक बार इस तरह की घटना ने उसे 05.11.2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए महिला आश्रय को फोन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसकी सूचना उसने तुरंत अपने भाई और चाचा को ईमेल के माध्यम से दी थी।

(9.14) प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता के साथ रहते हुए लगातार डर में जी रहा था। किसी न किसी बहाने वह उसे अपनी आत्महत्या की प्रवृत्ति की याद दिलाता रहता था। प्रतिवादी नंबर 2 को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए लगातार एक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा कई बार इन बातों को लिखा गया है, जिसमें 22.09.2015 का ईमेल और 30.06.2018 का व्हाट्सएप वार्तालाप शामिल है।

(9.15) अन्य मुद्दे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक साथ रहने के दौरान घर के अंदर छिपे हुए कैमरों की हैकिंग / जासूसी / रखने से प्रतिवादी नंबर 2 को डर हैं कि याचिकाकर्ता उसे और उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के घर के अंदर जानकारी प्राप्त करने और उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए भेदिया स्थापित किया।

(9.16) याचिकाकर्ता की गणना प्रकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने लगातार अपने स्वयं के कृत्यों और कर्मों से उनकी शादी को बाधित करने की कोशिश की है। उसे नाबालिग बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले कि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद

होता, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के पुराने घरेलू सहायक के साथ गुप्त तरीके से उसे एक फोन और 10,000 रुपये की राशि दी, जिसने प्रतिवादी नंबर 2 के चरित्रहीन महिला होने के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाईं, जिनके अलग-अलग पुरुषों के साथ कई संबंध हैं। याचिकाकर्ता ने उसके हर कदम पर नज़र रखने के लिए निजी जासूसों को भी लगाया और यादृच्छिक लोगों की तस्वीरें शूट कीं, जिसमें कहा गया था कि उसका इन सभी पुरुषों के साथ संबंध है।

(9.17) बच्चे की समग्र भलाई स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 2 के हाथों में है जो नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित में है जैसा कि अमेरिकी दूतावास, दिल्ली द्वारा पता लगाया गया है जब वे नाबालिग बच्चे से मिलने गए थे क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि नाबालिग बच्चे को प्रतिवादी नंबर 2 से 4 द्वारा बंदी बनाया जा रहा था। उनके द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई थी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग बच्चा एक खुश, स्वस्थ और स्मार्ट बच्चा है, जिसकी देखभाल उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। नाबालिग बच्चे की शारीरिक और मानसिक भलाई का आकलन एक विदेशी एजेंसी द्वारा किया गया है, जिसने कहा है कि वह सुरक्षित हाथों में है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। नाबालिग बच्चा वर्तमान में गुरुग्राम के अरावली के श्री राम स्कूल में नामांकित है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। भारत में स्कूल में बच्चे को दाखिला देने का निर्णय हमेशा याचिकाकर्ता का था क्योंकि उसका मानना है कि भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी है, क्योंकि वह खुद भारत में शिक्षित था।

(9.18) केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता और न ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने नाबालिग बच्चे की सर्जरी के बाद और यहां तक कि अदालत द्वारा 17.06.2020 के आदेश में यह कहे जाने के बाद भी नाबालिग बच्चे से मुलाकात की है कि याचिकाकर्ता बच्चे से मिलने आने, उसे बाहर ले जाने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 3 और प्रतिवादी नंबर 4 के घर में उनके साथ आ सकता है और रह सकता है। अभी तक याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नाबालिग बच्चे से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, एक बार भी नहीं। यह नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ता या उसके परिवार की रुचि के स्तर को दर्शाता है और स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के सच्चे इरादे को दर्शाता है जो प्रतिवादी नंबर 2 को परेशान करना है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विद्वान वकील ने तदनुसार याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है।

(9.19) अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के वकील ने निम्न मामलों की ***टिप्पणियों पर भरोसा किया है नित्या आनंद राघवन*** *बनाम* ***राज्य (एनसीटी***

ऑफ दिल्ली)[10]***; कनिका गोयल*** *बनाम* ***राज्य (एनसीटी दिल्ली);***[11] ***वीना कपूर*** *बनाम* ***वरिंदर कुमार कपूर***[12]***; प्रतीक गुप्ता*** *बनाम* ***शिल्पी गुप्ता***[13]***; रोक्सन शर्मा*** *बनाम* ***अरुण शर्मा***[14]***; लहरी सखामुरी*** *बनाम* ***सोभन कदली***[15]***; रुचि माजू बनाम संजीव माजू***[16] ***और यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य***[17]।

<u>एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट</u>

<u>(10)</u> न्यायमित्र के रूप में नियुक्त वकील श्री अनिल मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया है कि 14.07.2020 को, इस माननीय न्यायालय ने उन्हें कुछ तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पार्टियों के साथ बातचीत करने का समय दिया था। इसके अनुसरण में, उन्होंने 15.07.2020 से 07.08.2020 तक कई अवसरों पर फोन/व्हाट्सएप-ऐप कॉल पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के साथ अलग-अलग बातचीत की है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के साथ बातचीत करने के बाद उनके दृष्टिकोण का पता लगाने और उनके संबंधित रुख को सुनने के बाद, यह पता चलता है कि कोई पारस्परिक रूप से स्वीकार्य स्टैंड या तटस्थ स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता है जो दोनों पक्षों के लिए सहमत हो। इसलिए, उनके सर्वोत्तम प्रयासों और लंबी बातचीत के बावजूद, बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में दोनों पक्षों को स्वीकार्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

<u>(11)</u> इस न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए, अदालत मित्र ने अंतर-अभिभावकीय बाल संरक्षण के मुद्दों और भारतीय कानून में विदेशी अदालत के आदेशों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें इस संबंध में कानून के सभी संभावित पहलुओं और स्थिति का उल्लेख किया गया है। उक्त रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:-

> "अब प्रचलित स्थिति के अनुसार, पक्षों के बीच किसी भी विदेशी अदालत के आदेश / समझौते / व्यवस्था के बावजूद, भारतीय अदालतों के लिए अपने सर्वोत्तम हित में बच्चे के कल्याण को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का विकल्प खुला होगा, और विदेशी बच्चे के गृह देश में वापसी का कोई स्वचालित आदेश या निर्देश नहीं होगा। इस प्रक्रिया में, न्यायालयों की समिति के सिद्धांत का विवेकाधीन अनुप्रयोग हो सकता है और बच्चे के अंतिम कल्याण को निर्धारित करने के लिए निकटतम संपर्क के अधिकार क्षेत्र का सिद्धांत लागू होगा। यह कानून की नवीनतम स्थिति है।

---
[10] 2017 (8) SCC 454
[11] 2018 (9) SCC 578
[12] 1981 (3) SCC 92
[13] 2018 (2) SCC 309
[14] 2015 (8) SCC 318
[15] 2019 (7) SCC 311
[16] 2011 (6) SCC 473
[17] 2020 (3) SCC 67

चूंकि, भारत में अंतर-अभिभावकीय बाल निष्कासन को परिभाषित करने, मान्यता देने या पहचानने के लिए कोई क़ानून नहीं है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, भारतीय न्यायालय समय के साथ व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामलों पर निर्णय लेते रहे हैं, यह तय करने के लिए कि पार्टियों को क्या राहत दी जानी चाहिए। इसलिए, निर्णयों में भिन्नता है और कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं है। बाल सिद्धांत का कल्याण सर्वोपरि विचार होने के कारण, भारतीय न्यायालयों में एक सुसंगत दृष्टिकोण से हटने की प्रवृत्ति है और तदनुसार, तथ्यात्मक मैट्रिक्स और परिस्थितियों के आधार पर मिसालों को अलग या भिन्न किया जा सकता है, जो अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार, बाल अपहरण कानून में न्यायशास्त्र भिन्न होता है।

भारत में बाल संरक्षण मामलों में विकसित दर्पण आदेश न्यायशास्त्र, जिसमें अमेरिकी अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए दर्पण आदेश निर्देश पारित किए हैं, विदेशी न्यायालयों के अपने घरों में बच्चों की वापसी के लिए एक मिसाल स्थापित करने का एक संभावित तरीका हो सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा बाल निर्धारण के कल्याण और सर्वोत्तम हित के अधीन, भारतीय न्यायालयों के दूरदर्शी ज्ञान के माध्यम से न्यायिक तंत्र द्वारा विकसित दर्पण आदेश सूत्र, बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें प्यार, देखभाल और माता-पिता दोनों के स्नेह के साथ पारिवारिक जीवन प्रदान करने के लिए, विदेशी न्यायालयों में बच्चों की वापसी के लिए एक संभावित विधि के रूप में उद्धृत किया जा सकता है, जब तक कि इस विषय पर एक कानून अधिनियमित नहीं किया जाता है, और किसी भी संभावित कानून द्वारा कुछ न्यायिक कानूनी समाधान प्रक्रिया विकसित की जाती है।

संयुक्त/साझा पालन-पोषण को वरीयता देते हुए एकल अभिभावक अभिरक्षा की अवधारणा बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में नहीं है। लहरी सखामुरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हित की परिभाषा की व्याख्या की गई है जिसका अर्थ है कि "...शिशु या केवल कुछ साल के बच्चे के मामले में मां जो की प्राथमिक देखभाल करने वाली है, उसका प्यार ओर देखभाल काफी नहीं है । किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" की परिभाषा की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है "बच्चे के बारे में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार, उसके मूल अधिकारों और जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक भलाई और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास। इसलिए, किसी भी पारस्परिक रूप से सहमत पेरेंटिंग योजना द्वारा सह-पालन, साझा या संयुक्त हिरासत नाबालिग बच्चे के

सर्वोत्तम हित और कल्याण में है ताकि उसे माता-पिता दोनों के मौद्रिक और अन्य समर्थन के अलावा प्यार, देखभाल, ध्यान, पेरेंटिंग प्राप्त हो।

(12) **परमिंदर कौर बराड़ बनाम** ***पंजाब राज्य और अन्य शीर्षक वाले 2020 के सीआरडब्ल्यूपी संख्या 7400*** *मामले में इस अदालत ने* दिनांक***17.12.2020*** *को फैसला सुनाया* ***कि अंतर-देशीय बाल निष्कासन के मामले में बच्चे की*** हिरासत ***या बच्चे के प्रत्यावर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने की याचिका में कठिन प्रश्न शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं: -***

> "बच्चे की हिरासत का सवाल, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ***लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली: 2019 (7) एससीसी 311*** में कहा था, नाजुक मुद्दों को उठाता है जिन्हें अदालतों द्वारा निर्णय के लिए मुश्किल माना जाता है, खासकर जहां माता-पिता अनिवासी भारतीय हैं। जैसा कि देखा गया विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह ***मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय: 2017 (1) आरसीआर (सिविल) 1063,*** इस प्रकृति के मामलों में जबकि एक बच्चा, जिसे आदर्श रूप से माता-पिता दोनों की कंपनी की आवश्यकता होती है, माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीड़ित महसूस करता है, कई बार अदालत के लिए यह तय करना एक मुश्किल विकल्प बन जाता है कि हिरासत किसे दी जानी चाहिए। बच्चे केवल संपत्ति नहीं हैं: न ही वे अपने माता-पिता के लिए केवल खेलने की चीजें हैं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है। रोजी जैकब बनाम जैकब ए चक्रमक्कल मामले में अदालत: (1973) 1 एससीसी 840 और उनकी हिरासत के सवाल पर फैसला करने में उनके कल्याण पर सर्वोच्च विचार किया जाता है। हालांकि, कई बार मौजूदा परिस्थितियां इतनी हैरान करने वाली होती हैं कि परस्पर विरोधी मापदंडों को तौलना और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि संतुलन किस तरफ झुकता है।

(13) वर्तमान मामले में भी तथ्य और परिस्थितियां कम पेचीदा नहीं हैं जो इस न्यायालय के लिए परस्पर विरोधी मापदंडों को तौलना और यह तय करना मुश्किल बनाती हैं कि संतुलन किस तरफ झुकता है।

<u>बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की विचारणीयता का सवाल</u>

<u>(14)</u> अब, यह अच्छी तरह से तय है कि एक नाबालिग की हिरासत की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है, जिसे गलत तरीके से वंचित किया गया है। *(*संदर्भ- ***गौहर बेगम*** *बनाम* ***सुग्गी उर्फ नजमा बेगम***[18]***; मंजू तिवारी*** *बनाम* ***राजेंद्र तिवारी;***[19] ***सैयद सलीमुद्दीन बनाम डॉ रुखसाना***[20] ***और तेजस्विनी गौड़*** **और अन्य** बनाम ***शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य।*** [21]

---

[18] (1960) 1 SCC 597
[19] (1960) 1 SCC 597

(15) ***2020 एसएलपी की अपील संख्या 127 में 2019 की संख्या 7390 जिसका शीर्षक याशिता साहू*** *बनाम* ***राजस्थान राज्य और अन्य*** *है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने* ***एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंद एम. दिनशॉ और अन्य***[22] ***में अपने फैसलों का हवाला देते हुए 20.01.2020 को फैसला सुनाया; नित्या आनंद राघवन*** *बनाम* ***राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य***[23] और ***लहरी सखामुरी*** *बनाम* ***सोभन कोडाली*** [24], इन मामलों का संदर्भ देते हुए *इस तर्क को खारिज कर दिया कि यदि बच्चा किसी अन्य माता-पिता के संरक्षण में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सुनवाई योग्य नहीं है और माना कि अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकती है*

<u>पार्टियों के कानूनी अधिकार नहीं बल्कि बच्चे के हित और कल्याण का सबसे अच्छा विचार सर्वोपरि है।</u>

(16) ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल इस बात पर निर्भर नहीं है और आवश्यक रूप से केवल हिरासत की अवैधता के निर्धारण का पालन नहीं करता है और माता-पिता के कानूनी अधिकारों की परवाह किए बिना नाबालिग बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार पर आधारित है। ***होवर्थ*** *बनाम* ***नॉर्थकोट***[25]मामले में यह देखा गया कि बाल संरक्षण का निर्धारण करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र ऐसे मामलों में अपनी अंतर्निहित न्यायसंगत शक्तियों पर निर्भर करता है और अपने शिशु वार्ड की सुरक्षा के लिए राज्य के बल का उपयोग करता है, और जांच की प्रकृति और दायरे और परिणाम को पूरा करने के लिए निष्पक्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की मांग करता है। आगे यह देखा गया कि बाल संरक्षण मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूपों का उपयोग किसी कारावास या संयम की वैधता का परीक्षण करने के उद्देश्य से नहीं है, जैसा कि प्राचीन सामान्य कानून रिट, या क़ानून द्वारा विचार किया गया है, बल्कि प्राथमिक उद्देश्य एक साधन प्रस्तुत करना है जिसके द्वारा अदालत, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित कर सकता है कि बच्चे के कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या है, और निर्णय बच्चे के कल्याण में शामिल निष्पक्षता पर विचार करके किया जाता है, जिसके खिलाफ माता-पिता सहित किसी के भी कानूनी अधिकारों को समाप्त करने की अनुमति नहीं है। यह भी संकेत दिया गया था कि आमतौर पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का आधार अवैध हिरासत है; लेकिन एक बच्चे की हिरासत के लिए दायर की गई इस तरह की रिट के मामले में, कानून हिरासत की अवैधता से उतना चिंतित नहीं है

---

[20] 2001 (2) R.C.R. (Crl.) 591
[21] (SC): 2019 (3) R.C.R. (Civil) 104
[22] (1987) 1 SCC 42
[23] (2017) 8 SCC 454
[24] (2019) 7 SCC 311
[25] 152 Conn 460: 208 A 2nd 540: 17 ALR 3rd 758

जितना कि बच्चे के कल्याण के साथ। ***गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल***[26] *मामले* ***में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हावर्थ*** बनाम ***नॉर्थकोट*** *(*उपरोक्त*)* ***में की गई इन टिप्पणियों का उल्लेख किया*** *और कहा कि भारत में कानूनी स्थिति* उपरोक्त*सिद्धांत का अनुसरण करती है।*

(17) जब भी किसी नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित कोई प्रश्न उठता है चाहे वह अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 आदि के तहत नाबालिग बच्चे की हिरासत के लिए याचिका पर फैमिली कोर्ट/अभिभावक न्यायाधीश के समक्ष या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, तो मामले का निर्णय पार्टियों के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं बल्कि एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर किया जाना चाहिए। जो नाबालिग के हित और कल्याण के लिए सबसे अच्छा होगा। (*देखें एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंड एम दिनशॉ और अन्य। (1987) 1 SCC 42 और सैयद सलीमुद्दीन बनाम डॉ रुखसाना: 2001 (2) R.C.R. (Criminal) 591*)

<u>बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण का निर्धारण</u>

<u>(18)</u> बच्चे का कल्याण केवल पैसे से नहीं मापा जाना चाहिए और न ही केवल भौतिक आराम से। 'कल्याण' शब्द को इसके व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसकी शारीरिक भलाई पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह के बंधन की अवहेलना की जा सकती है। (पर लिंडले, एल.जे. ने ***McGrath***[27] में कहा कि कल्याण एक सर्वव्यापी शब्द है। इसमें भौतिक कल्याण शामिल है, दोनों एक सुखद घर और आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए संसाधनों की पर्याप्तता के अर्थ में और यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की पर्याप्तता के अर्थ में कि अच्छा स्वास्थ्य और उचित व्यक्तिगत गौरव बनाए रखा जाता है। हालांकि, जबकि भौतिक विचारों का अपना स्थान है, वे द्वितीयक मामले हैं। अधिक महत्वपूर्ण स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और मार्गदर्शन, गर्म और दयालु रिश्ते हैं, जो बच्चे के अपने चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। (प्रति हार्डी बॉयज़, जे. ***वॉकर*** *बनाम* ***वॉकर और हैरिसन***[28] में)

<u>(19)</u> **गौरव नागपाल** बनाम ***सुमेधा नागपाल*** [29] *मामले में* माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

> "42. ... अदालत को न केवल कानूनी आधार पर इस मुद्दे को देखना है, ऐसे मामलों में उन मुद्दों को तय करने के लिए मानवीय कोण प्रासंगिक हैं। अदालत

[26] 2008(4) R.C.R.(Civil) 928
[27] (1893) 1 Ch 143)
[28] (1981) New Zealand Recent Law 257
[29] 2008 (4) R.C.R. (Civil) 928

तब इस बात पर जोर नहीं देती है कि पक्ष क्या कहते हैं, उसे एक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना होगा जो नाबालिग के कल्याण के उद्देश्य से है। जैसा कि हाल ही में मौसमी मोइत्रा गांगुली के मामले (उपरोक्त) में देखा गया है, अदालत को बच्चे की सामान्य संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को महत्व देना होगा, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के अलावा, नैतिक और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना होगा। वे दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं तो समान हैं।

43. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त 'कल्याण' शब्द का शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे इसके व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण को भी तौलना चाहिए। अदालत के साथ-साथ इसकी शारीरिक भलाई के लिए देखना चाहिए। हालांकि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले न्यायालय के रास्ते में बाधा बन सकता है।

(20) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***नील रतन कुंडू*** *बनाम* ***अभिजीत कुंडू मामले*** [30] में पैराग्राफ 52 में नाबालिग बच्चों की हिरासत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया है: -

"नाबालिग बच्चों की हिरासत **को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत**

56. हमारे निर्णय में, एक बच्चे की हिरासत से संबंधित कानून काफी अच्छी तरह से तय किया गया है और यह यह है: नाबालिग की हिरासत के बारे में एक कठिन और जटिल प्रश्न का फैसला करते समय, कानून की अदालत को प्रासंगिक विधियों और उससे रहने वाले अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का फैसला केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता है। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय स्पर्श से हल करने की आवश्यकता है। हिरासत के मामलों से निपटने के दौरान एक अदालत न तो क़ानूनों से बाध्य होती है और न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से और न ही मिसालों से। एक नाबालिग के उचित अभिभावक का चयन करते समय, बच्चे का कल्याण और कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। अभिभावक का चयन करते समय, अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दे। लेकिन भौतिक सुख-

[30] 2008 (3) RCR (Civil) 936

सुविधाओं से ऊपर, नैतिक और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे समान रूप से हैं, या हम कह सकते हैं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार। यदि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता या निर्णय बनाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है, तो अदालत को इस तरह की वरीयता पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के पास होना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।

(21) लहरी सखामुरी ***बनाम** सोभन कदली **मामले में***[31] माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"43. अभिव्यक्ति "बच्चे का सर्वोत्तम हित" जो हमेशा होता है सर्वोपरि विचार वास्तव में अपने अर्थ में व्यापक है और यह प्राथमिक देखभाल देने वाले का प्यार और देखभाल नहीं रह सकता है, यानी माँ, शिशु या बच्चे के मामले में जो केवल कुछ साल का है। किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (9) में "बच्चे के सर्वोत्तम हित" की परिभाषा की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ है "बच्चे के बारे में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार, उसके मूल अधिकारों और जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास"।

49. माता-पिता के लिए समान रूप से बच्चों के कल्याण का आकलन करने के लिए न्यायालयों द्वारा जिन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा जाना है, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ चित्रित किया जा सकता है, जैसे (1) परिपक्वता और निर्णय; (2) मानसिक स्थिरता; (3) स्कूलों तक पहुंच प्रदान करने की क्षमता; (4) नैतिक चरित्र; (5) समुदाय में निरंतर भागीदारी प्रदान करने की क्षमता; (6) वित्तीय पर्याप्तता और अंतिम लेकिन कम से कम कारक जो बच्चे के साथ संबंध को शामिल करते हैं, एक व्यक्ति के रूप में माता-पिता की विशेषताओं के विपरीत।

(22) 2020 की सिविल अपील संख्या 3559 जिसका शीर्षक स्मृति ***मदन कंसागरा बनाम पेरी कंसागरा** है, में 28.10.2020 को दिए गए फैसले **में*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"11.3. बच्चे के सर्वोत्तम हित के मुद्दे को तय करने के लिए, न्यायालय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखेगा, जैसे कि बच्चे की उम्र; बच्चे की राष्ट्रीयता; क्या बच्चा समझदार उम्र का है और बुद्धिमान वरीयता देने में सक्षम है; बच्चे के समग्र विकास और विकास के लिए उपलब्ध पर्यावरण और रहने की स्थिति; माता-पिता में

[31] 2019 (7) SCC 311

से किसी एक के वित्तीय संसाधन जो एक प्रासंगिक मानदंड भी होंगे, हालांकि एकमात्र निवारक कारक नहीं होगा; और बच्चे की भविष्य की संभावनाएं।

अंतर-देशीय बच्चे को हटाने और प्रत्यावर्तन का मुद्दा

(23) भारत ने अंतर-राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 या माता-पिता की जिम्मेदारी और बच्चों के संरक्षण पर हेग कन्वेंशन, 1996 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर मामलों या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता को चुनौती देने वाली अपीलों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन नाबालिग बच्चों, जिन्हें विदेशों से निकालकर भारत लाया गया था, को उस देश में वापस भेजने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के प्रश्न पर विचार किया है जहां से उन्हें हटा दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया है कि उच्च न्यायालय बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार को ध्यान में रखते हुए हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है और यहां तक कि विदेशी न्यायालय के आदेश को भी बच्चे के कल्याण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत में कार्यवाही और यूएसए कोर्ट द्वारा पारित आदेश

(24) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने बेंटन काउंटी, अर्कांसस, यूएसए के सर्किट कोर्ट से संपर्क किया और उक्त अदालत ने दिनांक 03.02.2020 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"अब 3 फरवरी, 2020 को, यह मामला अदालत के समक्ष आता है और अदालत अच्छी तरह से और पर्याप्त रूप से सलाह देती है और निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:

1. न्यायालय के पास पार्टियों पर अधिकार क्षेत्र है और विषय वस्तु और स्थान यहां उचित है।

2. प्रतिवादी ने पार्टियों के नाबालिग बच्चे को भारत में हटा दिया है और वादी की सहमति के बिना वहां रह रहा है।

3. प्रतिवादी ने बच्चे को वादी से अलग कर दिया है, जो बच्चे की भलाई के लिए हानिकारक है।

4. वादी को अदालत के अगले आदेश लंबित होने तक नाबालिग बच्चे, आदित्य किरण की प्राथमिक देखभाल, संरक्षण और नियंत्रण से सम्मानित किया जाता है।

5. प्रतिवादी आदित्य किरण को वादी को तुरंत वापस कर देगा।

6. किसी भी पक्ष के अनुरोध पर तुरंत सुनवाई निर्धारित की जाएगी।

(25) बेशक, नाबालिग बच्चा एक अमेरिकी नागरिक है। अरकंसास के बेंटन काउंटी में क्षेत्राधिकार की विदेशी अदालत पहले से ही हिरासत की कार्यवाही से ग्रस्त है। भारत में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के विवाह के विघटन या नाबालिग बच्चे के संरक्षण के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(26) तथ्य यह है कि विदेशी अदालत का एक पहले से मौजूद आदेश है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में न्यायालय एक कारक है जिसे याचिकाकर्ता के पक्ष में माना जाना चाहिए, लेकिन यह नाबालिग बच्चे के प्रत्यावर्तन के सवाल को बाधित नहीं करता है ताकि इसे अनुमति दी जा सके, जिस प्रश्न को नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के परीक्षण पर तय किया जाना है।

(27) **लहरी सखामुरी *बनाम सोभन कोडाली (*उपरोक्त*) मामले*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों की समानता, अंतरंग जुड़ाव, नाबालिग बच्चे की हिरासत, माता-पिता और बच्चे की नागरिकता आदि के संबंध में मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाली विदेशी अदालतों द्वारा पारित आदेशों के सिद्धांत, बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के विचार की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस करने का निर्देश के परिणामस्वरूप। बच्चे को कोई भी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होना चाहिए।

<u>क्या संक्षिप्त जांच करनी है या विस्तृत जांच करनी है।</u>

<u>(28)</u> नित्या आनंद राघवन ***बनाम*** *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य मामले* ***में*** [32] माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कानून को दोहराया:-

> "24............. कोर्ट ने कहा है कि भारत ने अभी तक "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर 1980 के हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जहां तक गैर-कन्वेंशन देशों का संबंध है, कानून यह है कि जिस देश में बच्चे को हटाया गया है, उस देश की अदालत को बच्चे के कल्याण से संबंधित गुण-दोष के प्रश्न को सर्वोपरि महत्व के रूप में मानना चाहिए और विदेशी अदालत के आदेश को केवल एक कारक के रूप में मानना चाहिए, जब तक कि अदालत बच्चे के हितों में सारांश अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना उचित न समझे और इसकी शीघ्र वापसी हो उसके कल्याण के लिए है। सारांश क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और इस राय से कि उसके समक्ष शुरू की गई कार्यवाही निकटता में थी और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाए जाने और अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लाए जाने के तुरंत बाद दायर की गई थी, बच्चे ने यहां जड़ें नहीं जमाई हैं और

[32] (SC): 2017 (3) RCR (Civil) 798

आगे कहा कि बोली जाने वाली भाषा या सामाजिक में अंतर के कारण अपने मूल राज्य में लौटना बच्चे के कल्याण में होगा। रीति-रिवाज और संपर्क या ऐसे अन्य मूर्त कारण जिनके लिए वह आदी रहा है। ऐसे मामले में अदालत को बच्चे के सर्वोपरि कल्याण के गुण-दोष की विस्तृत जांच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे की वापसी का निर्देश देकर उस जांच को विदेशी अदालत पर छोड़ दें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि असाधारण मामलों में अदालत अभी भी बच्चे को मूल राज्य में वापस करने के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर सकती है और विशेष रूप से उस संबंध में विदेशी अदालत के पहले से मौजूद आदेश के बावजूद, अगर वह संतुष्ट है कि बच्चे की वापसी उसे नुकसान के गंभीर जोखिम में डाल सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत में अदालतें, जिनके अधिकार क्षेत्र में नाबालिग को लाया गया है, को "आमतौर पर" गुण-दोष के सवाल पर विचार करना चाहिए, बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विदेशी अदालत के पहले से मौजूद आदेश को केवल एक कारक के रूप में मानना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में- चाहे वह एक सारांश जांच हो या एक विस्तृत जांच - बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। इस प्रकार, इस मुद्दे की जांच करते समय भारत में अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र में लाए गए बच्चे की वापसी की राहत को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर वह संतुष्ट है कि बच्चा अब अपने नए वातावरण में बस गया है या यदि यह बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाएगा या अन्यथा बच्चे को असहनीय स्थिति में डाल देगा या यदि बच्चा काफी परिपक्व है और इसकी वापसी पर आपत्ति करता है। हम उपरोक्तप्रदर्शनी के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं।

26. इस न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि यदि बच्चे को भारत के भीतर लाया गया है, तो भारत में न्यायालय (ए) संक्षिप्त जांच कर सकते हैं या (बी) हिरासत के सवाल पर विस्तृत जांच कर सकते हैं। सारांश जांच के मामले में, न्यायालय बच्चे को उस देश में वापस लाने का आदेश देना उचित समझ सकता है जहां से उसे हटा दिया गया था जब तक कि ऐसी वापसी बच्चे के लिए हानिकारक नहीं दिखाई जाती है। दूसरे शब्दों में, सारांश जांच के मामले में भी, यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह उस देश में बच्चे की वापसी की राहत को अस्वीकार कर दे, जहां से उसे हटा दिया गया था, भले ही विदेशी न्यायालय द्वारा बच्चे की वापसी का पहले से मौजूद आदेश हो। एक विस्तृत जांच में, न्यायालय इस गुण-दोष की जांच करने के लिए बाध्य है कि बच्चे के सर्वोपरि हित और कल्याण कहां हैं और बच्चे की वापसी के लिए विदेशी न्यायालय के पहले से मौजूद आदेश के तथ्य को केवल परिस्थितियों में से एक के रूप में मानते हैं। किसी भी मामले में, न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न (जिस देश में बच्चे को हटा दिया

जाता है) बच्चे के कल्याण के अनुसार इस मुद्दे का उत्तर देना है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।

(29) नित्या ***आनंद राघवन*** *बनाम* ***राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य*** (उपरोक्त) ***मामले में अपने पहले के फैसले*** को लागू करते हुए ***प्रतीक गुप्ता बनाम शिल्पी गुप्ता और अन्य***[33] ***के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार फैसला सुनाया.*** -

"32. अपने मूल देश से हटाए गए बच्चे के प्रत्यावर्तन के मुद्दे पर न्यायिक निंदा का आधार स्पष्ट रूप से इसके समग्र कल्याण, अदालतों के संयोजन के सिद्धांत और "अंतरंग संपर्क और निकटतम चिंता" के सिद्धांतों की प्रमुख अनिवार्यता पर आधारित है। यद्यपि न्यायालयों के समूह का सिद्धांत और उपर्युक्त सिद्धांत एक विदेशी न्यायालय को उस क्षेत्र से जोड़ते हैं जहां से एक बच्चे को हटा दिया जाता है, ऐसे कारक हैं जो बच्चे के संरक्षण और प्रत्यावर्तन के मुद्दे पर निर्णय लेने में ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट नहीं है कि कभी भी अभिभावी निर्धारक बच्चे का कल्याण और हित होगा। दूसरे शब्दों में, इन सिद्धांतों/सिद्धांतों के आह्वान को प्रत्येक मामले के असंख्य परिचर तथ्यों और परिस्थितियों की कसौटी पर आंका जाना चाहिए, अंतिम सजीव चिंता बच्चे का कल्याण है, अन्य कारकों को स्वीकार किया जाता है। यद्यपि प्रत्यावर्तन के मुद्दे के निर्णय की प्रक्रिया में, एक अदालत एक संक्षिप्त जांच को अपनाने और बच्चे को उसके मूल देश में तत्काल बहाल करने का आदेश देने का चुनाव कर सकती है, यदि आवेदक / माता-पिता अपनी पहल में त्वरित और सतर्क हैं और मौजूदा परिस्थितियां बच्चे के कल्याण की अत्यधिक आवश्यकता में इस तरह के पाठ्यक्रम को फिर से सही ठहराती हैं, इस तरह के पाठ्यक्रम को कानून में लागू किया जा सकता है, अगर प्रासंगिक कारकों की एक सहज समझ इसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व पर अपरिवर्तनीय, प्रतिकूल और पूर्वाग्रहपूर्ण प्रभाव की गवाही देती है, इस प्रकार इसे दृश्यमान, निरंतर और अपूरणीय हानिकारक और शून्यवादी आक्षेपों के लिए उजागर करती है। दूसरी ओर, यदि आवेदक/माता-पिता सुस्त हैं और मूल देश से बच्चे को हटाने और उसके प्रत्यावर्तन के लिए उठाए गए कदमों के बीच काफी समय अंतराल है, तो अदालत बच्चे पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक पहलुओं की विस्तृत जांच को प्राथमिकता देगी, क्योंकि इस बीच समय बीतने के साथ, इसने अपेक्षित रूप से देश और इसके विशिष्ट परिवेश में जड़ें जमा ली थीं, इस प्रकार इसके दायरे में इसके संवारने की प्रक्रिया पर इसका प्रभाव पड़ा।

<u>वर्तमान मामले में राहत</u>

---

[33] (2018) 2 SCC 209

(30) वर्तमान मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाना चाहिए, जिसमें नाबालिग बच्चे की मूल देश में वापसी को निर्देशित या अस्वीकार किया गया है, पार्टियों के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर कि क्या नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित का सर्वोपरि विचार संयुक्त राज्य अमेरिका में वापसी में निहित है। या भारत में रहना जारी रखा। उक्त प्रश्न का निर्धारण करते समय इस न्यायालय के पास एक संक्षिप्त जांच या विस्तृत जांच का सहारा लेने का विकल्प है और विकल्प का प्रयोग किया जाना है और उक्त प्रश्न का निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित के सर्वोपरि विचार पर निर्णय लेते हुए किया जाना है। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लेने पर, मेरा विचार है कि इसमें शामिल प्रश्नों पर संक्षिप्त जांच का सहारा लेकर निर्णय लिया जाना चाहिए और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है।

(31) वर्तमान मामले में 21.01.2016 को पैदा हुआ नाबालिग बच्चा, जो अब लगभग साढ़े पांच साल का है, जन्म से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। नाबालिग बच्चा दोनों के साथ अमेरिका में रह रहा था। नाबालिग बच्चे ने साढ़े पांच साल में से तीन साल से अधिक की अवधि अमेरिका में और ढाई साल भारत में बिताई है। न तो अवयस्क बच्चे द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताए गए तीन वर्षों की अवधि और न ही नाबालिग बच्चे द्वारा अपने प्रारंभिक वर्षों में भारत में बिताए गए ढाई साल की अवधि को संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत के सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक वातावरण के साथ उसका पूर्ण एकीकरण कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता अमेरिका में अपने प्रत्यावर्तन की मांग कर रहा है, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 उसे भारत में रहने की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है और इस संबंध में दिए गए आधारों पर फैसला किया जा सकता है।

नाबालिग-आदित्य किरण की मेडिकल कंडीशन

(32) **माना मेडिकल एसोसिएट्स की दिनांक** 31.01.2019 **की रिपोर्ट में उल्लिखित वर्तमान मामले में नाबालिग बच्चे-आदित्य किरण को बाएं ओर हल्के और दाईं ओर मध्यम से गंभीर द्विपक्षीय हाइड्रोनफ्रोसिस नेफ्रोसिस के मामले के रूप में निदान किया गया था। उनकी हालत में सर्जरी के जरिए सुधार की जरूरत थी।**

(33) अमेरिका में सर्जरी स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 ने मैक्स अस्पताल साकेत में डॉ अनुराग कृष्णा द्वारा भारत में सर्जरी करने का फैसला किया। बेशक, प्रतिवादी नंबर 2 नाबालिग बच्चे के साथ अकेले यात्रा नहीं

कर सकता था। तदनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहमति फॉर्म निष्पादित किया गया था, जिसमें बच्चे को 05.02.2019 और 26.09.2019 की तारीखों के बीच प्रतिवादी नंबर 2 के साथ भारत की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

(34) नाबालिग बच्चे ने 05.02.2019 को यात्रा सहमति के संदर्भ में प्रतिवादी नंबर 2 के साथ भारत की यात्रा की। 14.03.2019 को मैक्स अस्पताल, साकेत में उनकी सुधारात्मक सर्जरी हुई। डॉ. अनुराग कृष्णा ने प्रमाण पत्र जारी किया कि नाबालिग-आदित्य किरण, जिनके पास द्विपक्षीय हाइड्रोनफ्रोसिस और दाईं ओर पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन रुकावट के साथ घोड़े की नाल की किडनी थी, 14.03.2021 को आरटी पाइलोप्लास्टी से गुजरना पड़ा। उन्होंने उन्हें 12.07.2019 को फॉलोअप के दौरान देखा और वह ठीक हैं, उन्हें सर्जरी के 6-7 महीने बाद नए अल्ट्रासाउंड और रीनल स्कैन के साथ समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(35) महाजन इमेजिंग सेंटर डीटीपीए की दिनांक 31.01.2020 की रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्तरिपोर्ट में यह धारणा निम्नानुसार दर्ज की गई थी:-

"हॉर्स शो किडनी दो भागों को जोड़ने वाले कार्यशील पैरेन्काइमा के साथ।

हल्के रूप से बिगड़ा हुआ कॉर्टिकल फ़ंक्शन के साथ अवशिष्ट हाइड्रोनफ्रोसिस दिखाने वाला गैर-बाधित दाहिना भाग।

संरक्षित कॉर्टिकल फ़ंक्शन के साथ आंशिक रूप से बायाँ भाग बाधित है।

13.2.2019 को किए गए पिछले डीटीपीए स्कैन की तुलना में, कॉर्टिकल फ़ंक्शन और सही मात्रा के जल निकासी पैटर्न में सुधार देखा गया है।

(36) प्रतिवादी संख्या 2 ने दावा किया है कि हालांकि 31.01.2020 को अंतिम रिपोर्ट में मामूली सुधार देखा गया है, लेकिन कोई चूक नहीं हो सकती है क्योंकि यह नाबालिग बच्चे के जीवन के लिए बेहद घातक हो सकता है क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि वह अत्यधिक पानी पी सकता है जिससे उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की चरम चिकित्सा देखभाल और पर्यवेक्षण प्रदान करना संभव नहीं होगा, यही कारण है कि भारत में नाबालिग बच्चे की मेडिकल सर्जरी कराने के लिए एक कॉल लिया गया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने यह भी दावा किया है कि प्रतिवादी नंबर 2 की मां, प्रतिवादी नंबर 4, जिसके साथ नाबालिग बच्चा रहता है, एक डॉक्टर है। उसका भाई भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर है और उत्तरदाताओं नंबर 2 से 4 के करीब रहता है। प्रतिवादी नंबर 2 का भाई भी एक डॉक्टर है। नाबालिग बच्चे का भारत के गुरुग्राम में रहना हित में है।

(37) हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने यह दिखाने के लिए कोई और मेडिकल रिपोर्ट या चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड पेश नहीं किया है कि नाबालिग बच्चे को सामान्य आवधिक समीक्षा के अलावा किसी और नियमित चिकित्सा / सर्जिकल उपचार की आवश्यकता है, जिसे किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में भी व्यवस्था करना मुश्किल नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने शपथ ली है कि उसने डॉ. अनुराग कृष्णा से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि नाबालिग बच्चे को अमेरिका लौटने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए, अवयस्क बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यावर्तित करना उसकी चिकित्सा स्थिति या भारत में उसके चिकित्सा / शल्य चिकित्सा उपचार के अलगाव के कारण उसके लिए हानिकारक नहीं होगा और भारत में उसका निरंतर रहना उसके भविष्य के चिकित्सा / शल्य चिकित्सा उपचार के लिए उसकी कथित खराब चिकित्सा स्थिति के कारण आवश्यक नहीं है, यदि ऐसा आवश्यक हो और इसलिए, यह तथ्य कि दादी और उनके भाई और नाबालिग बच्चे के मामा डॉक्टर हैं, प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में संतुलन को झुकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

<u>**याचिकाकर्ता का भारत में बसने का दृष्टिकोण**</u>

<u>(38) </u>प्रतिवादी संख्या 2 ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता चाहता था कि नाबालिग बच्चे की परवरिश पूरी तरह से भारतीय जड़ों में हो और वह चाहती थी कि उसका बच्चा भारत में पढ़ाई करे। याचिकाकर्ता के निर्देश पर प्रतिवादी नंबर 2 ने इससे पहले वर्ष 2017 और 2018 में भारत का दौरा किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में स्थायी रूप से बसना था। 2018 में नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ता की इच्छा के अनुसार भारत में प्री स्कूल में नामांकित किया गया था। अप्रैल, 2019 में याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे के लिए प्री स्कूल 'पल्लवन' का चयन किया। याचिकाकर्ता ने भारत में बसने के लिए बैंगलोर में जमीन खरीदी और प्रतिवादी नंबर 2 को प्रतिवादी नंबर 3 से जमीन खरीदने के लिए धन मांगने के लिए प्रेरित किया। याचिकाकर्ता चाहता था कि प्रतिवादी नंबर 2 भारत में काम करना शुरू करे और एक अद्भुत घर बनाने के लिए पैसे कमाए, जैसा कि 11.01.2019 के व्हाट्सएप संदेश में उल्लेख किया गया है।

<u>(39) </u>भले ही ई-मेल और व्हाट्सएप संदेशों को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भरोसा किया गया है, लेकिन माना जाता है कि याचिकाकर्ता बेंटन कंट्री, अर्कांसस, यूएसए का स्थायी निवासी है और वर्तमान में वॉलमार्ट लैब्स, बेंटनविले, यूएसए में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। याचिकाकर्ता ने सेटलमेंट के लिए सेंटरटन, अर्कांसस, यूएसए में घर खरीदा था, जो प्रतिवादी नंबर 2 के दावे को नकारता है कि याचिकाकर्ता तुरंत स्थायी रूप से भारत में बसने का इच्छुक है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 को बैंगलोर में जमीन खरीदने और जमीन खरीदने के लिए

धन की व्यवस्था करने के लिए कहा, जो निकट भविष्य में भारत में स्थानांतरित होने और स्थायी रूप से बसने की उनकी योजना को नहीं दर्शाता है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना जारी रखने के अपने दृष्टिकोण के याचिकाकर्ता के दावे को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सहमति फॉर्म द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें 26.09.2019 को प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे की वापसी की आवश्यकता होती है। यात्रा योजना में कोई भी बदलाव दोनों पक्षों की चर्चा और सहमति के अधीन था। यात्रा योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया था और दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता के बिना अकेले नाबालिग बच्चे के साथ भारत की यात्रा नहीं कर सकता था, अगर ऐसी कोई यात्रा सहमति नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने उसके तहत भारत की यात्रा की है, लेकिन उसके संदर्भ में लौटने में विफल रही है, उसे अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ऐसा करने के लिए अपने कानूनी और न्यायसंगत दायित्व के अनुसार नाबालिग बच्चे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना होगा।

याचिकाकर्ता की तेजमिजाज आत्मघाती प्रकृति

(40) प्रतिवादी संख्या 2 ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता को तुनकमिजाज समस्याएं हैं और वह छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, उसका गुस्सा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी और अपने नाबालिग बच्चे की जान का डर है, एक बार इस तरह की घटना ने उसे 05.11.2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला आश्रय में कॉल करने के लिए मजबूर किया था, जिसके बारे में उसने अपने भाई और चाचा को तुरंत ईमेल के माध्यम से सूचित किया था। प्रतिवादी नंबर 2 लगातार याचिकाकर्ता के साथ डर में रह रहा था क्योंकि किसी न किसी बहाने से, वह उसे अपनी आत्महत्या की प्रवृत्ति की याद दिलाता रहा। प्रतिवादी नंबर 2 को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए लगातार एक हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जिसका उल्लेख 22.09.2015 के ईमेल और 30.06.2018 के व्हाट्सएप वार्तालाप में भी किया गया था। अमेरिका में एक साथ रहने के दौरान घर के अंदर छिपे हुए कैमरों की हैकिंग/जासूसी /रखने के कई अन्य मुद्दों ने भी प्रतिवादी नंबर 2 को डरा दिया कि याचिकाकर्ता उसे और नाबालिग बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

(41) हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने यूएसए में किसी भी प्राधिकरण को की गई कोई शिकायत पेश नहीं की है। प्रतिवादी नंबर 2 ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ उसकी शादी को भंग करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, जिसमें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है और परिणामस्वरूप भावनात्मक आघात है, को दूसरों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी प्रवृत्ति को शामिल नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने सेंटर फॉर साइकोलॉजी द्वारा दी गई दिनांक 21.10.2020 की अपनी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट पेश की है, जिसमें निष्कर्ष

निकाला गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल समस्याओं से मुक्त है और उसे इस समय कोई निदान योग्य मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। वह अवसाद, चिंता से मुक्त है और कोई आत्मघाती विचारधारा की रिपोर्ट नहीं करता है।

(42) नतीजतन, यह मानने के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए, नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यावर्तन उसके हित और कल्याण के अनुसार नहीं होगा।

बच्चे के कल्याण के संबंध में अमेरिकी दूतावास की रिपोर्ट की प्रासंगिकता

(43) प्रतिवादी नंबर 2 ने दावा किया है कि बच्चे की समग्र भलाई स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 2 के हाथों में है जो नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित में है जैसा कि अमेरिकी दूतावास, दिल्ली द्वारा पता लगाया गया है जब वे नाबालिग बच्चे से मिलने गए थे क्योंकि याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि नाबालिग बच्चे को प्रतिवादी नंबर 2 से 4 द्वारा बंदी बनाया जा रहा था। उनके द्वारा एक विस्तृत कल्याण रिपोर्ट दी गई थी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग बच्चा एक खुश, स्वस्थ और स्मार्ट बच्चा है, जिसकी देखभाल उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। नाबालिग बच्चे की शारीरिक और मानसिक भलाई का आकलन एक विदेशी एजेंसी द्वारा किया गया है, जिसने कहा है कि वह सुरक्षित हाथों में है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है।

(44) दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि कल्याणकारी यात्रा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यात्रा एक बाल संरक्षण मूल्यांकन नहीं है और आगे यह कहते हुए इसे योग्य बनाया कि दौरा परामर्श अधिकारी बाल संरक्षण या सामाजिक कार्य में प्रशिक्षित नहीं है जैसा कि अस्वकीरण में उल्लेख किया गया है।

(45) दिनांक 17.12.2019 की रिपोर्ट के अस्वीकरण के अवलोकन से पता चलता है कि परामर्श दाता संबंधों पर वियना कन्वेंशन अमेरिकी दूतावास और / या महावाणिज्य दूतावास के कर्मियों को अमेरिकी नागरिकों से मिलने के लिए अधिकृत करता है ताकि उनके ठिकाने और सामान्य कल्याण का पता लगाया जा सके। नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में, परामर्श दाता कर्मियों को बच्चे के स्थानीय माता-पिता या अभिभावक की अनुमति होनी चाहिए। परामर्श दाता अधिकारी, जो आमतौर पर बाल संरक्षण, सामाजिक कार्य या इसी तरह के अन्य विषयों में प्रशिक्षित नहीं होता है, अपनी टिप्पणियों की एक रिपोर्ट लिखता है। यह रिपोर्ट बाल संरक्षण मूल्यांकन नहीं है।

(46) उपर्युक्त अस्वीकरण को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.12.2019 की कल्याण रिपोर्ट को बाल संरक्षण मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट उत्तरदाता संख्या 3 और 4 की उपस्थिति में प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत पर आधारित है और आगंतुकों द्वारा व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित है, जिन्हें बाल संरक्षण, सामाजिक कार्य या अन्य समान विषयों में प्रशिक्षित नहीं किया गया था। इसलिए,

अमेरिकी दूतावास के आगंतुकों द्वारा तैयार की गई कल्याणकारी रिपोर्ट नाबालिग बच्चे के कल्याण के सवाल को तय करने में कोई महत्व नहीं रखती है।

नाबालिग बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान देना।

(47) प्रतिवादी संख्या 2 ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नाबालिग बच्चे को ऐसी व्यक्तिगत देखभाल और पर्यवेक्षण प्रदान करना संभव नहीं होगा जैसा कि भारत में प्रतिवादी नंबर 2 से 4 द्वारा उसे दिया जा रहा है।

(48) हालांकि, अमेरिकी दूतावास के विजिटिंग परामर्श दाता की दिनांक 17.12.2019 की कल्याणकारी रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने विजिटिंग परामर्श दाता को बताया कि उसकी चाची नाबालिग बच्चे को स्कूल से उठाती है और उसे हर दिन घर लाती है और पूरे दिन उसके साथ रहती है, जबकि मां और दादा-दादी काम पर होते हैं। नाबालिग बच्चे का एक घरेलू सहायक है जो उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसके साथ खेलता है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यहां तक कि प्रतिवादी नंबर 2 और उसके माता-पिता भी नाबालिग बच्चे को पूरे दिन व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान नहीं दे रहे हैं।

(49) याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.06.2020 को हलफनामा दायर किया है कि याचिकाकर्ता के पास यूएसए में अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए आवश्यक कौशल भी है। याचिकाकर्ता के पास स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प भी है, जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर पूरे समय बच्चे की देखभाल कर सके। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की मां श्रीमती उषा हनुमंथराया के पास 23.02.2024 तक वैध अमेरिकी वीजा है और उन्होंने इस अदालत में नाबालिग बच्चे की देखभाल करने की इच्छा व्यक्त की है।

(50) इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं है कि अवयस्क बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में उचित व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान नहीं दिया जा सकता है और इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नाबालिग बच्चे के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान की कमी के आधार पर नाबालिग बच्चे के प्रत्यावर्तन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 के घर के अंदर जानकारी प्राप्त करने और उसे गलत तरीके से फंसाने के लिए भेदिया स्थापित किया।

(51) प्रतिवादी नंबर 2 ने अपनी मानसिक और शारीरिक क्रूरता के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और याचिकाकर्ता द्वारा विवाहेतर संबंध के झूठे आरोप लगाए हैं, जिसमें कैमरे लगाने, नौकरानी के माध्यम से निगरानी, निजी जासूसों को कार्य आदि के बारे में विस्तृत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने मानसिक या शारीरिक क्रूरता के आधार पर अपनी शादी को भंग करने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है और भारत या

संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस या अदालत में कोई शिकायत नहीं की है। विवाह विच्छेद या नाबालिग बच्चे के संरक्षण के लिए याचिका पर इन कथनों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नंबर 2 को अमेरिकी अदालत के समक्ष नाबालिग बच्चे की हिरासत के अपने अधिकार के आधार को साबित करना होगा, जिसके पास इसके बारे में अधिकार क्षेत्र था और जिसके समक्ष कार्यवाही अब लंबित है, खासकर जब प्रतिवादी नंबर 2 ने याचिकाकर्ता के साथ अपने विवाह को भंग करने और नाबालिग बच्चे की हिरासत के लिए भारत में कोई कार्यवाही दायर नहीं की थी।

(52) नाबालिग बच्चा कुछ समय से भारत में रह रहा है। लगभग ढाई साल जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लगभग डेढ़ साल की लॉक-डाउन/प्रतिबंध/सोशल डिस्टेंसिंग की अवधि भी शामिल थी। भारत में नाबालिग बच्चे का प्रवास भारत के सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक वातावरण के साथ उसके अनुकूलन और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत कम अवधि है। यदि नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस भेज दिया जाता है, तो उसे सामाजिक हलकों से अलग शिक्षा की पूरी तरह से विदेशी प्रणाली के अधीन नहीं किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 2 से अलग होने के कारण नाबालिग बच्चे के मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होने की संभावना है- उसकी मां, जो उसके लिए प्राथमिक देखभाल कर्ता है और जिसकी देखभाल में वह अपने जन्म के बाद से ही रहा है, लेकिन उसकी मां (प्रतिवादी नंबर 2) ने पहले ही उसे अपने पिता के प्यार और स्नेह से गलत तरीके से वंचित कर दिया है, जिसके साथ नाबालिग बच्चा उसके जन्म से लेकर भारत में भेजे जाने तक रहता था। अपने नाना-नानी (उत्तरदाता संख्या 3 और 4) और अन्य रिश्तेदारों का अपने पिता से दूर रहने के लिए मजबूर करने को उसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अमेरिका का नागरिक होने के नाते नाबालिग बच्चे के पास संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर बेहतर भविष्य की संभावनाएं होंगी। जब तक नाबालिग बच्चे को तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस नहीं भेजा जाता है, तब तक उसकी अंतर्निहित क्षमताओं और संकायों को एक अथाह झटका लगेगा। अपने मूल देश- संयुक्त राज्य अमेरिका के वातावरण में संवारने की प्राकृतिक प्रक्रिया उनके मानसिक और शारीरिक संकायों के व्यापक और अनुकूल विकास के लिए अपरिहार्य है। नाबालिग बच्चे की संयुक्त राज्य अमेरिका में वापसी को निर्देशित करने के लिए बाध्यकारी कारण हैं जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है और इस तरह की वापसी को किसी भी तरह से नाबालिग बच्चे के लिए हानिकारक नहीं दिखाया गया है। भारत में नाबालिग बच्चे का बने रहना उसके समग्र विकास और संवारने के लिए हानिकारक होगा और उसके हित और भविष्य की संभावनाओ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि नाबालिग बच्चे के संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने से उसे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या सांस्कृतिक नुकसान

होगा। वर्तमान याचिका दायर करने में कोई अनुचित और अतार्किक देरी हुई है जिससे याचिकाकर्ता दावा की गई राहत से वंचित हो जाए।

(53) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और सारांश जांच के आधार पर, मेरा विचार है कि यह नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित में होगा कि नाबालिग बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस लाने के लिए आदेश पारित किया जाए। जहां से उसे हटाया गया था और यह उचित होगा कि अभिभावक की नियुक्ति/नाबालिग बच्चे को माता-पिता में से किसी एक को सौंपने के प्रश्न को संयुक्त राज्य अमेरिका में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा कल्याण और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सर्वोच्च विचार के आधार पर निर्णय के लिए छोड़ दिया जाए।

(54) मामले के इन उपरोक्ततथ्यों और परिस्थितियों में, ***नित्या आनंद राघवन*** *बनाम* ***राज्य (एनसीटी दिल्ली)*** [34]***; कनिका गोयल*** *बनाम* ***राज्य (एनसीटी दिल्ली);*** [35] ***वीना कपूर*** *बनाम* ***वरिंदर कुमार कपूर*** [36]***; प्रतीक गुप्ता*** *बनाम* ***शिल्पी गुप्ता*** [37]***; रोक्सन शर्मा*** *बनाम* ***अरुण शर्मा*** [38]***; लहरी सखामुरी*** *बनाम* ***सोभन कदली*** [39]***; रुचि माजू बनाम*** *संजीव माजू**और*** [40] और **यशिता साहू *बनाम राजस्थान राज्य*** [41]**,** की टिप्पणी ***पर प्रतिवादी संख्या*** 2 ***से*** 4 ***के*** विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है।

(55) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है:-

(i) प्रतिवादी नंबर 2 को 30.09.2021 को या उससे पहले नाबालिग बच्चे के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने का निर्देश दिया जाता है;

(ii) यदि प्रतिवादी नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने का विकल्प चुनता है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 और नाबालिग बच्चे की वापसी के लिए यात्रा और आकस्मिक खर्च वहन करेगा और हिरासत याचिका के निर्णय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके रहने का खर्च भी वहन करेगा और याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को अंतर-देशीय हटाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ कोई आपराधिक / अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं करेगा;

---

[34] 2017 (8) SCC 454
[35] 2018 (9) SCC 578
[36] 1981 (3) SCC 92
[37] 2018 (2) SCC 309
[38] 2015 (8) SCC 318
[39] 2019 (7) SCC 311
[40] 2011 (6) SCC 473
[41] 2020 (3) SCC 67

(iii) यदि प्रतिवादी नंबर 2 उपरोक्तनिर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी नंबर 2, 01.10.2021 को या ऐसी अन्य तारीख पर याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे की हिरासत और उसका पासपोर्ट सौंप देगा, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है;

(iv) यदि प्रतिवादी नंबर 2, 01.10.2021 को या याचिकाकर्ता द्वारा सहमत किसी अन्य तारीख पर नाबालिग बच्चे की हिरासत और उसका पासपोर्ट सौंपने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी नंबर 1 प्रतिवादी नंबर 2 से नाबालिग बच्चे की हिरासत और पासपोर्ट ले लेगा और याचिकाकर्ता द्वारा सहमत तारीख पर नाबालिग बच्चे की हिरासत और पासपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंप देगा।

(v) नाबालिग बच्चे की हिरासत और उसका पासपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपे जाने पर, याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को यूएसए ले जाने का हकदार होगा;

(vi) यदि नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नुकसान / क्षति आदि के आधार पर याचिकाकर्ता या प्रतिवादी नंबर 1 को नहीं सौंपा जाता है, तो याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकरण से प्रतिलिपि पासपोर्ट जारी करने का हकदार होगा; और

(vii) अवयस्क बच्चे के संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर, दोनों में से कोई भी पक्ष अभिभावक की नियुक्ति और नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में उचित आदेशों के लिए अमेरिकी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(56) 20.01.2020 को यशिता साहू ***बनाम*** *राजस्थान राज्य और अन्य शीर्षक वाली 2020* ***की आपराधिक अपील संख्या 127 में*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"18. बच्चा हिरासत की लड़ाई में पीड़ित है। अहंकार की इस लड़ाई और दो पति-पत्नी के बीच बढ़ती तीखी लड़ाई और मुकदमेबाजी में, हमारा अनुभव बताता है कि अधिक बार, माता-पिता जो अन्यथा अपने बच्चे से प्यार करते हैं, एक तस्वीर पेश करते हैं जैसे कि दूसरा पति या पत्नी एक खलनायक है और वह अकेले बच्चे की हिरासत का हकदार है। इसलिए अदालत को पति-पत्नी में से प्रत्येक द्वारा कही गई बातों के बारे में बहुत भिन्न होना चाहिए।

19. एक बच्चे, विशेष रूप से कोमल वर्षों के बच्चे को दोनों माता-पिता के प्यार, स्नेह, साथ, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह न केवल बच्चे की आवश्यकता है, बल्कि उसका मूल मानव अधिकार भी है। सिर्फ इसलिए कि माता-पिता एक-दूसरे के साथ युद्ध में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे को दो माता-पिता में से किसी

एक की देखभाल, स्नेह, प्यार या सुरक्षा से वंचित किया जाना चाहिए। एक बच्चा एक निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे एक माता-पिता से दूसरे में उछाला जा सकता है। हर जुदाई, हर पुनर्मिलन का बच्चे पर दर्दनाक और मनोदैहिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अदालत यह तय करने से पहले प्रत्येक परिस्थिति को बहुत सावधानी से तोलती है कि बच्चे की हिरासत दोनों माता-पिता के बीच कैसे और किस तरह से साझा की जानी चाहिए। यहां तक कि अगर हिरासत एक माता-पिता को दी जाती है, तो दूसरे माता-पिता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मुलाकात अधिकार होना चाहिए कि बच्चा दूसरे माता-पिता के संपर्क में रहता है और दो माता-पिता में से किसी एक के साथ सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संपर्क नहीं खोता है। यह केवल चरम परिस्थितियों में है कि एक माता-पिता को बच्चे के साथ संपर्क से वंचित किया जाना चाहिए। यदि एक माता-पिता को बच्चे के साथ किसी भी मुलाकात के अधिकार या संपर्क से वंचित किया जाना है, तो कारण बताए जाने चाहिए। हिरासत के मामलों से निपटने वाली अदालतों को हिरासत के मुद्दों पर निर्णय लेते समय स्पष्ट रूप से मुलाकात के अधिकारों की प्रकृति, तरीके और विशिष्टताओं को परिभाषित करना चाहिए।

22. 'मुलाकात अधिकार' के अलावा, 'संपर्क अधिकार' भी बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहां माता-पिता दोनों अलग-अलग राज्यों या देशों में रहते हैं। आधुनिक युग में संपर्क अधिकारों की अवधारणा टेलीफोन, ईमेल या वास्तव में संपर्क द्वारा होगी, हमें लगता है कि संपर्क की सबसे अच्छी प्रणाली, यदि पार्टियों के बीच उपलब्ध है तो वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए। इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता के साथ, चलचित्र सम्प्रेषण अब बहुत आम है और बच्चों की हिरासत के मुद्दे से निपटने वाली अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस माता-पिता को बच्चे की हिरासत से वंचित किया जाता है, वह अपने बच्चे से जितनी बार हो सके बात करने में सक्षम होना चाहिए। जब तक कि एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए विशेष परिस्थितियां न हों, जिस माता-पिता को बच्चे की हिरासत से वंचित किया जाता है, उसे हर दिन 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चे से बात करने का अधिकार होना चाहिए। यह बच्चे और माता-पिता के बीच बंधन को बनाए रखने और सुधारने में मदद करेगा, जिसे हिरासत से वंचित किया गया है। यदि उस बंधन को बनाए रखा जाता है, तो बच्चे को छुट्टियों या छुट्टियों के दौरान एक घर से दूसरे घर जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका उद्देश्य यह है कि यदि हम बच्चे को दो माता-पिता के साथ एक खुशहाल घर प्रदान नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को एक माता-पिता के साथ दो खुशहाल घरों का लाभ दें।

(57) **याशिका साहू** के ***मामले (*** उपरोक्त ***) में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए*** यह आदेश दिया जाता है कि जब तक अमेरिकी अदालत के समक्ष कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के

लिए किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया जाता है और उस पर सक्षम अधिकार क्षेत्र के अमेरिकी न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम/अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक प्रतिवादी नंबर 2 बच्चे से मिलने का हकदार होगा और हर रविवार को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उसकी अस्थायी हिरासत में रहेगा या यदि प्रतिवादी नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है और रहता है या नाबालिग बच्चे को हर दिन शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे (संयुक्त राज्य अमेरिका समय) के बीच लगभग आधे घंटे के लिए चलचित्र सम्प्रेषण करता है जैसा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच सहमति हुई है। यदि प्रतिवादी नंबर 2 अमेरिका नहीं लौटता है और अमेरिका में नहीं रहता है और ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को साल में एक बार प्रतिवादी नंबर 2 और उसके नाना/अन्य रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत लाएगा, तो याचिकाकर्ता को भारत लाना होगा।

(58) हालांकि, इस आदेश में कुछ भी पार्टियों को नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए दलों द्वारा सहमत किसी भी संयुक्त परवरिश योजना को अपनाने से नहीं रोकेगा जैसे कि नाबालिग बच्चे के प्रवेश की व्यवस्था छात्रावास की सुविधा के साथ किसी स्कूल में और छुट्टियों के दौरान उससे मिलने और छुट्टी के दौरान उसे हिरासत में लेना, जैसा कि स्कूल अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में टिप्पणियां वर्तमान रिट याचिका के निपटान के उद्देश्य से की गई हैं और किसी भी अदालत या प्राधिकरण को बच्चे की हिरासत या कल्याण के सवाल से जुड़े किसी अन्य मामले के निपटान में बाध्य नहीं करेगा।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

करमबीर सिंह,
(अनुवादक)